RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 26 APRIL TO 2 MAY 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 31 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

इस बार बंपर जीएसटी कलेक्शन की उम्मीद, मार्च में रिकॉर्ड 9.09 करोड़ ई-वे बिल जारी Page 3

बदल गए हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत टैक्स-बेनेफिट Page 4

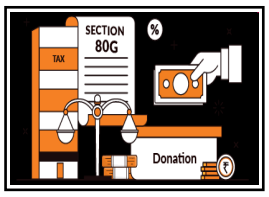

आम आदमी को महंगाई से नहीं मिलेगी राहत Page 5

editoria!

लॉजिस्टिक में प्रगति

भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न मानकों में निरंतर बेहतरी हो रही है. बैंक की लॉजिस्टिक परफॉरमेंस इंडेक्स, 2023 में 139 देशों में भारत 38वें स्थान पर आ गया है. इस सूचकांक में 2014 में भारत 54वें और 2018 में 44वें स्थान पर रहा था. यह सूचकांक तकनीक और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के आधार पर तैयार किया जाता है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अक्टूबर, 2021 में महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना की शुरुआत की थी, जो आवागमन के विभिन्न माध्यमों का राष्ट्रव्यापी विस्तार एवं विकास करने का राष्ट्रीय मास्टर प्लान है. पिछले साल सितंबर में एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी निर्धारित की गयी. यह देश की ऐसी पहली नीति है. लॉजिस्टिक नीति की घोषणा के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह नीति आठ वर्षों के कार्यों का परिणाम है. लॉजिस्टिक में औद्योगिक उत्पादन और वितरण में सहायक सभी चीजें शामिल होती है, जैसे- योजना बनाना, भंडारण करना, कामगारों और अन्य संसाधनों का आवागमन, उत्पादित वस्तु को बाजार तक ले जाना आदि. अभी हमारे सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) में लॉजिस्टिक के खर्च की हिस्सेदारी 14 से 18 फीसदी है, जबकि अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में यह आंकड़ा आठ प्रतिशत के आसपास होता है. ऐसा होने का मुख्य कारण देश हाल तक किसी तरह की लॉजिस्टिक नीति का नहीं होना रहा है. अब अगर हम लॉजिस्टिक नीति के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित कर दें, तो 2030 में हम दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के स्तर पर आ सकते हैं. इस नीति का दूसरा लक्ष्य लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत को शीर्ष के 25 देशों में शामिल करना है. आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं. सरकार की प्राथमिकता में लॉजिस्टिक कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान केवल इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर रेल और सड़क मार्ग के नेटवर्क का विस्तार हो रहा है. साथ ही, वास्तविक नियंत्रण रेखा से निकट बसे इलाकों में ब्रॉडबैंड लगाया जा रहा है. सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जोरों पर है. लॉजिस्टिक परफॉरमेंस इंडेक्स की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारत सरकार ने 2015 से दोनों ओर के बंदरगाहों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है. आशा है कि भारत जल्दी ही इस इंडेक्स में शीर्ष देशों में शामिल होगा.

अमेरिकी चेतावनी के बाद रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत?

UAE ने भी दिया झटका

एजेंसी

रूस पर लागू आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद भारत भारी मात्रा में रूसी तेल आयात कर रहा है। लगातार पिछले छह महीनों से रूस भारत के लिए नंबर 1 तेल सप्लायर है। क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने के बाद भारत भी प्राइस कैप से ऊपर भुगतान कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी कंपनियां सुनिश्चित करें कि रूसी तेल का निर्यात प्राइस कैप के भीतर ही हो। रूस - यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत रूस से भारी मात्रा में रियायती कीमतों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन अमेरिकी चेतावनी और यूएई के अपनी करेंसी दिरहम के इस्तेमाल की मनाही के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच तेल व्यापार अंत की ओर है। रूस से तेल खरीदना भारत के लिए धीरे-धीरे ही सही लेकिन मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पिछले सप्ताह अमेरिका की चेतावनी के बाद से भारत सरकार इस समस्या का हल खोज रही है। भारत के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले सप्ताह ही अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा था कि हम इस बात से अवगत हैं कि कुछ रूसी तेल प्राइस कैप से ऊपर निर्यात किया गया है। सभी कंपनियां सुनिश्चित करें कि रूसी तेल का निर्यात प्राइस कैप के भीतर ही हो। यानी रूसी तेल 60 डॉलर प्रति बैरल या उससे कम कीमत पर खरीदा जाए। दरअसल, हाल ही में रूस और तेल उत्पादक देशों के संघ ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में प्रतिदिन लगभग 36 लाख बैरल की कटौती की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से ही तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ओपेक प्लस के इस कदम के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने का असर यह हुआ है कि रूसी तेल की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि भारत भी रूसी तेल का भुगतान निर्धारित प्राइस कैप से ऊपर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका की चेतावनी ने भारतीय रिफाइनरी कंपनियां को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो रूसी तेल खरीदने से पहले इसके परिणाम पर विचार करें। वहीं, इंडियन पॉलिसीमेकर के लिए भी इसका संज्ञान लेना जरूरी हो गया है, ताकि प्राइस कैप के उल्लंघन के बाद होने वाले व्यापक असर से पहले इस समस्या का समाधान निकाला जाए। क्योंकि यूएई ने भी अपनी मुद्रा दिरहम को प्राइस कैप से ऊपर खरीदे जा रहे तेल के भुगतान में इस्तेमाल करने से भारत को मना कर दिया है।

रूस से तेल खरीदने में भारत को क्या आ रहीं समस्याएं

भारत रूस से तेल खरीदने में दो तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। पहला- माइक्रो और दूसरा- मैक्रो। पहला तेल ट्रांसपोर्टिंग के फिजिकल पार्ट से संबंधित हैं। दूसरा-ऊर्जा सुरक्षा, रुपये से कारोबार में समस्याएं एवं पश्चिमी देशों के साथ रिलेशन मेंटेन रखना। प्रतिदिन रूस से लगभग 20 लाख बैरल तेल खरीदना धीरे-धीरे भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। रूस से व्यापार करने में सबसे ज्यादा समस्याएं भुगतान से संबंधित हैं। चूंकि, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू है. इसलिए रूस को भुगतान करने के लिए भारत को अन्य मुद्राओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। वर्तमान में भारतीय रिफाइन कंपनियां रूसी तेल के भुगतान के लिए दिरहम मुद्रा का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ब्रिटेन ने यूएई पर दबाव बनाया है। जिसके बाद यूएई ने भारतीय रिफाइन कंपनियों को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि उनके बैंकों या मुद्रा का उपयोग प्राइस कैप से अधिक कीमत वाले रूसी तेल के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, अमेरिक ने यूएई से रूसी कंपनियों और बैंकों को लाइसेंस देने से भी मना करने के लिए कहा है।

हालांकि, भारत ने कोशिश की कि रूस को रुपए में भुगतान किया जाए। लेकिन रूसी बैंक भारतीय रुपये में व्यापार करने से कतराते हैं। क्योंकि भारत से रूस का आयात उस अनुपात में नहीं है, जिस अनुपात में रूस से भारत का। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पिछले सप्ताह एक एवेंट में कहा था कि रूस के साथ तेल व्यापार में आने वाली प्रमुख समस्याओं में से प्रमुख समस्याएं- भुगतान, लॉजिस्टिक और सर्टिफिकेशन हैं।

निर्यात पर लगा सकता है रोक

अमेरिकी समेत कई पश्चिमी देश दिसंबर 2022 से रूसी तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल की प्राइस कैप लगाए हुए हैं। यानी 60 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर तेल आयात पर उस तेल के लिए कंपनियों को शिपिंग, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। पेरिस स्थित मार्केट एनालिटिक्स फर्म ख्ज्ञी के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2023 से भारत औसतन 18 लाख बैरल प्रति दिन रूसी तेल आयात कर रहा है। भारत के लिए समस्या यह है कि पिछले कुछ दिनों से रूसी तेल की कीमत प्राइस कैप के उल्लंघन के दायरे में है। यूराल ग्रेड का कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। जिससे भारत निर्यात होने वाले रूसी तेल में कमी आई है। चूंकि, अगले 45 से 60 दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। इसलिए इसका व्यापक असर जून से देखने को मिलेगा।

अमेरिकी चेतावनी के बाद भारतीय तेल कंपनियां सतर्क

भारत ने इससे पहले रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन वर्तमान में प्राइस कैप पर जी- 7 देशों एवं अमेरिका की बढ़ती निगरानी ने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दिसंबर 2022 में जी-7 देशों ने लॉडिंग पॉइंट पर 60 डॉलर प्रति बैरल से अधिक कीमत वाले रूसी तेल के निर्यात पर रोक लगा दी थी।

जीएसटी चोरी पर एक्शन में सरकार, डेटा एनालिटिक्स की मदद से होगी 'मिसिंग लिंक' की पहचान

नई दिल्ली। एजेंसी

गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) भुगतान में चोरी और विशेष क्षेत्र में पूरी सप्लाई चेन में पर्याप्त जीएसटी का भुगतान हो रहा है या नहीं, यह पता लगाने के लिए जीएसटी अधिकारी अब डेटा एनालिटिक्स की मदद ले रहे हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 23 में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी का पता चला था जिसके बाद से जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने तत्काल प्रभाव से चोरी को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी थी ताकि इस मामले को जल्द से जल्द सुधारा जा सके।

समाचार एजेंसी को एक जीएसटी अधिकारी ने बताया कि 'मिसिंग लिंक' की पहचान करने के लिए 'एंड-टू-एंड' एनालिटिक्स और 'गैप विश्लेषण' का उपयोग किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस मामले में सुधारा जाए। अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद जीएसटी विभाग जरूरत पड़ने पर कानून या टैरिफ में भी कुछ बदलाव कर सकता है और इसे अनुमोदन के लिए जीएसटी परिषद के सामने रख सकता है ताकि चोरी की जांच की जा सके। जीएसटी अधिकारी ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में चोरी का मामला सामने आता है तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

साल-दर-साल बढ़ रहा है जीएसटी की चोरी

कर अधिकारियों ने साल-दर-साल जीएसटी चोरी में वृद्धि देखी है और अब यह बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 1.01 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। अगर वित्त वर्ष 2022-23 की बात करें तो डीजीजीआई के अधिकारियों ने 21,000 करोड़ रुपये की वसूली की है। इभ 23 में जीएसटी चोरी के केस 14,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं 2021-22 में जीएसटी चोरी के केस 12,574 और 2020-21 में केस की संख्या 12,596 थी।

3.08 लाख करोड़ की पकड़ी गई जीएसटी की चोरी

पिछले महीने लोक सभा को दिए जवाब में वित्त मंत्रालय ने कहा कि जुलाई 2017 से फरवरी 2023 के बीच कुल 3.08 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता चला है जिसमें से 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वसूली कर ली गई है। जीएसटी अधिकारियों ने फरवरी 2023 तक पिछले साढ़े पांच साल में कर चोरी के आरोप में अभी तक 1,402 लोगों को गिरफ्तार किया है।

आरबीआई की बड़ी कार्रवाई

4 बैंकों पर लगाया 44 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के कारण 4 सहकारी बैंकों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं- तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और बारां नागरिक सहकारी बैंक. इनमें से सबसे अधिक 16 लाख रुपये का जुर्माना चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर लगा है. आरबीआई ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा, बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बकौल आरबीआई, बैंक निर्धारित समय के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में तय पैसों को ट्रांसफर करने में विफल रहा और उसे देरी से स्थानांतरित किया. बैंक ने एक अन्य प्रेस रिलीज में कहा, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक पर 'जमा पर ब्याज दर' के निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर 13 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

तमिलनाडु स्टेट एपेक्स पर जुर्माना क्यों

तमिलनाडु स्टेट एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर भी उसी कारण से जुर्माना लगा है जिस वजह से बॉम्बे मर्केंटाइल पर लगाया गया है. इसके साथ ही बैंक निर्धारित समयसीमा के भीतर धोखाधड़ी की सूचना नाबार्ड को देने में भी विफल रहा और देरी से इसकी सूचना दी. वहीं, राजस्थान के बारां स्थित बारां नागरिक सहकारी बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

क्या होगा इसके ग्राहकों पर असर

बैंकों पर कार्रवाई के बाद बड़ा सवाल उठता है कि क्या इससे बैंक के ग्राहकों पर कोई असर होगा. आरबीआई ने इसे लेकर भी स्थिति साफ कर दी है.आरबीआई ने कहा है कि इन बैंकों पर मानदंडों की अनदेखी के लिए जुर्माना लगाया है. हालांकि, इसका इन बैंकों के ग्राहकों द्वारा किये जा रहे लेनदेन पर कोई असर नहीं होगा.

अल नीनो से बन सकते हैं सूखे जैसे हालात!

आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर बढ़ेगा जोखिम: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। एजेंसी

तमाम चुनौतियों के बावजूद विकास की पटरी पर तेज गति से रफ्तार भर रहे भारत को कृषि उपज में कमी, कीमतों में वृद्धि और भू-राजनीतिक परिवर्तन जैसे संभावित जोखिमों से सतर्क रहने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को मासिक आर्थिक समीक्षा में आगाह करते हुए कहा, अल नीनो (स्पैनिश में लिटिल ब्वॉय) से सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। इससे कृषि उपज में कमी के साथ कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। भू-राजनीतिक परिवर्तन और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता जैसे संभावित जोखिम भी भारत की चिंता बढ़ा सकते हैं। ये तीनों कारक अनुमानित आर्थिक वृद्धि और महंगाई के परिणामों के अनुकूल संयोजन को प्रभावित कर सकते हैं। मंत्रालय ने समीक्षा के मार्च संस्करण में कहा, चालू वित्त वर्ष में वास्तविक वृद्धि दर 6.5 फीसदी रहने का अनुमान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के अनुमानों के अनुरूप है। हालांकि, कुछ कारक इस अनुमान को प्रभावित कर सकते हैं।

अर्थव्यवस्था : सबसे तेज रहेगी वृद्धि दर

रिपोर्ट के मुताबिक, महामारी और भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 में मजबूत रही है। अब भी इसमें मजबूती देखी जा रही है। भारतीय जीडीपी के 7 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि की तुलना में अधिक है।

चालू खाता घाटे में सुधार, महंगाई के दबाव में कमी और नीतिगत दरों में वृद्धि का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूती वाली बैंकिंग प्रणाली से वृहद आर्थिक स्थिरता बढ़ती दिख रही है। इससे आर्थिक वृद्धि दर और भी टिकाऊ बनी है।

विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी, कैड घटा

मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बाहरी मोर्चे पर देश की स्थिति अच्छी है। चालू खाता घाटे (कैड) में गिरावट आई है। इसके अलावा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।?इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हो रही है।

महंगाई पर काबू पाने में सरकार के त्वरित कदमों से मिली मदद

रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-22 में पूरे वर्ष के लिए खुदरा महंगाई दर 5.5 फीसदी रही थी। 2022-23 में यह बढ़कर 6.7 फीसदी पहुंच गई। लेकिन, 2022-23 की दूसरी छमाही में यह 6.1 फीसदी ही रही, जबकि पहली छमाही में 7.2 फीसदी रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जिसों के दामों में नरमी, सरकार के त्वरित कदमों और आरबीआई की मौद्रिक सख्ती ने घरेलू महंगाई पर काबू पाने में मदद की है।

बैंकिंग क्षेत्र पर बढ़ी निगरानी

वित्तीय क्षेत्र पर रिपोर्ट में कहा गया कि आरबीआई ने संपत्ति के आकार की परवाह किए बिना बैंकिंग क्षेत्र पर निगरानी बढ़ाई है। केंद्रीय बैंक के दायरे में आने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ी है। बैंकों पर दबाव का परीक्षण भी समय-समय पर किया जाता है।

इसलिए अमेरिका व यूरोप से अलग हैं भारतीय बैंक

मंत्रालय ने कहा, जमा की तेजी से निकासी की आशंका नहीं है, क्योंकि 63 फीसदी जमा वैसे परिवार करते हैं, जो जल्द निकासी नहीं करते हैं। इन सभी कारकों की वजह से भारत के बैंक अमेरिका और यूरोप के बैंकों से अलग हैं।

PM Cares में सरकारी कंपनियों ने डाले 2900 करोड़ से ज्यादा, पेट्रोल-गैस कंपनियां सबसे बड़ी दानी

नई दिल्ली। कोविड के संकट काल में लोगों को जरूरी मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने मार्च 2020 में पीएम केयर फंड बनाया था. हालांकि उस समय इसकी काफी आलोचना हुई थी क्योंकि देश में पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ है. लेकिन 2019-20 से 2021-22 के बीच इस राहत फंड में सरकारी कंपनियों ने भर-भरकर पैसा दिया है. सरकारी कंपनियों का योगदान 2,900 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है. पीएम केयर्स में आए दान को लेकर प्राइमइन्फोबेस डॉट कॉम ने एक एनालिसिस किया है. इसके हिसाब से जिन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी है या जो सरकार के अधीन हैं, ऐसी 57 कंपनियों ने इस फंड में कुल 2,913.6 करोड़ रुपये दान दिए हैं. ये पीएम केयर्स फंड में आए कुल दान का करीब 59.3 प्रतिशत है.

पेट्रोल-गैस कंपनी सबसे बड़ी दानी

पीएम केयर्स में 247 कंपनियों ने दान दिया है. 2 साल के अंदर इस फंड में 4,910.5 करोड़ रुपये दान आया है. पीएम केयर में सबसे ज्यादा दान देने का काम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ध्ठण) ने किया है. कंपनी ने कुल 370 करोड़ रुपये दान में दिए हैं. इसके अलावा टॉप-5 कंपनियों में 330 करोड़ रुपये देकर एनटीपीसी दूसरे नंबर पर, 275 करोड़ रुपये देकर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तीसरे नंबर पर, 265 करोड़ रुपये देकर इंडियन ऑयल चौथे नंबर पर और 222.4 करोड़ रुपये के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पांचवे नंबर पर रही है.

पीएम केयर्स फंड का बवाल

पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर पहले ही विवाद हुआ. फिर चीनी कंपनियों से दान लेने और इसकी संसद के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होने की वजह से भी इसकी काफी आलोचना हुई. दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट जमा की, जिसमें कहा गया कि इस फंड का नियंत्रण भारत सरकार के पास नहीं है. 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में भी सरकार ने यही बात कही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि इस फंड में किसी तरह के सरकारी पैसे का दान नहीं लिया गया है.

इस बार बंपर जीएसटी कलेक्शन की उम्मीद, मार्च में रिकॉर्ड 9.09 करोड़ ई-वे बिल जारी

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले साल के बाद इस साल भी जीएसटी कलेक्शन नया रिकॉर्ड बना सकता है। मार्च महीने में बने कुल ई-वे बिलों की संख्या 9.09 करोड़ पहुंच गई है। यह संख्या फरवरी में बने कुल ई-वे बिलों से 11 फीसदी अधिक है। जीएसटीएन के आंकड़ों के अनुसार मार्च महीने में 9.09 करोड़ ई-वे बिल बने है। इससे अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनने के आसार बन गए हैं। वित्तवर्ष 2023-24 के पहले महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े 1 मई को जारी किए जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार, मार्च महीने में 1.6 लाख करोड़ रुपये का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन हुआ था। तब फरवरी में 8.18 करोड़ ई-वे बिल बने थे। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में रिकॉर्ड 1.67 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। उस दौरान मार्च महीने में करीब 7.81 करोड़ ई-वे बिल जारी किए गए थे। दिसंबर 2022 में आंकड़ा 8.41 करोड़ ई-वे बिल का था।

ई-वे बिल में 11 फीसद का इजाफा

जीएसटीएन के आंकड़ों के मुताबिक राज्यों के भीतर सामान भेजने के लिए मार्च में 5.78 करोड़ ई-वे बिल और दूसरे राज्यों में माल भेजने के लिए 3.3 करोड़ परमिट बनाए गए। इस तरह मार्च महीने में बने कुल ई-वे बिलों की संख्या 9.09 करोड़ पहुंच गई है। यह संख्या फरवरी में बने कुल ई-वे बिलों से 11 फीसदी अधिक है। यह संख्या एक रिकॉर्ड है, जो वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में मजबूत आर्थिक गतिविधियों का संकेत देती है।

सरकार ने उठाए कदम

मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक सरकार ने न केवल जीएसटी वसूली को तकनीक के जरिए ज्यादा प्रभावी बनाया है, बल्कि कारोबारी खुद भी आसान व्यवस्था होने की वजह से कर देना पसंद कर रहे हैं। ऐसे में इस महीने बड़े पैमाने पर जीएसटी कलेक्शन होने की उम्मीद जताई जा रही है।

ये रही बढ़ोतरी की प्रमुख वजह

मार्च वित्तवर्ष का आखिरी कारोबारी महीना होता है। ऐसे में कारोबारी गतिविधियों में तेज रही हैं। जानकारों की राय में आखिरी महीना होने की वजह से तमाम कारोबारियों पर साल का बिक्री का लक्ष्य हासिल करने का दबाव रहता है। ऐसे में उत्पादन भी तेज रहता है। यही वजह है कि पिछले साल के बाद इस साल भी जीएसटी कलेक्शन नया रिकॉर्ड बना सकता है।

क्या होता है ई-वे बिल

वस्तुओं की आवाजाही के लिए कंप्यूटर आधारित चालान को ई-वे बिल कहते हैं। एक शहर से दूसरे शहर या राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक की वस्तुओं की आवाजाही के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। इसको किसी भी समय कहीं से बैठे ट्रैक किया जा सकता है कि संबंधित वाहन कहां है। इससे कर चोरी पर अंकुश लगने के साथ-साथ परिवहन कंपनियों की लागत भी घटती है।

अब ओवरड्रॉफ्ट की रकम से भी होगा यूपीआई पेमेंट

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट सिस्टम के दायरे का विस्तार करते हुए बड़ा फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अब ओवरड्रॉफ्ट फेसिलिटी का इस्तेमाल UPI Payment के लिए भी किया जा सकता है। इसका मतलब, अगर किसी अकाउंट होल्डर को ओवरड्रॉफ्ट की सुविधा मिली है तो वह इस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकता है। बता दें कि हर बैंक अकाउंट के साथ यह सुविधा नहीं मिलती है। हालांकि, हर बैंक की तरफ से लिमिटेड ग्राहकों को यह सुविधा जरूर मिलती है।

रिजर्व बैंक UPI पेमेंट इकोसिस्टम के विस्तार की योजना पर लगातार काम कर रहा है। डिजिटल रीटेल ट्रांजैक्शन में ळझ्ड का दबदबा है और 75 फीसदी ट्रांजैक्शन इसकी मदद से किए जाते हैं। अभी तक UPI का इस्तेमाल मुख्य रूप से डिपॉजिट अकाउंट्स की मदद से होता है। अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तभी यूपीआई की मदद से ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के ताजा आदेश के बाद अगर किसी अकाउंट के साथ क्रेडिट लाइन यानी ओवरड्रॉफ्ट की सुविधा उपलब्ध है तो इस रकम से भी UPI ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं।

गवर्नर दास ने मॉनिटरी पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि यह पहले से मंजूर कर्ज से जुड़ा है। वर्तमान में डिपॉजिट अकाउंट्स के अलावा कुछ मामलों में WALLET और प्रीपेड कार्ड की मदद से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। गवर्नर दास ने कहा कि RBI बहुत जल्द इस संबंध में डीटेल निर्देश जारी करेगा।

डिजिटल बैंकिंग की स्वीकार्यता में तेजी आएगी

इस बारे में भारतीय बैंक संघ (IBA) के अध्यक्ष ए के गोयल ने कहा कि बैंकों में पहले से मंजूर कर्ज सुविधा को शामिल कर यूपीआई के दायरे के विस्तार का उद्देश्य इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाना है। पे नियरबाइ के फाउंडर और CEO आनंद कुमार बजाज ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से बैंकों में प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन की अनुमति देकर यूपीआई के दायरे का विस्तार करने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है। इससे ग्राहकों के लिए कर्ज मिलने की सुविधा तक पहुंचना आसान होगा. इससे देश में डिजिटल बैंकिंग की स्वीकार्यता में तेजी आएगी।

रुपया शुरुआती कारोबार में छह पैसे टूटकर 82.01 प्रति डॉलर पर

मुंबई। एजेंसी

स्थानीय शेयर बाजारों में गिरावट के रुख और विदेशी पूंजी की निकासी के बीच बुधवार को रुपया शुरुआती कारोबार में छह पैसे टूटकर 82.01 प्रति डॉलर पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 82.00 प्रति डॉलर पर कमजोर खुलने के बाद 82.01 प्रति डॉलर पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद स्तर की तुलना में छह पैसे की गिरावट है। मंगलवार को रुपया 81.95 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.04 प्रतिशत गिरकर 101.82 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.37 प्रतिशत चढ़कर 81.07 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 407.35 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

अब एक साथ कई 4 डिवाइसेस पर चला सकेंगे एक Whatsapp! जानें कैसे

नई दिल्ली। एजेंसी

Can run one Whatsapp in many phone संदेश मंच व्हॉट्सएप ने ऐसा फीचर पेश किया है, जिसके तहत उसके उपभोक्ता एक खाते को एक साथ कई फोन पर चला सकेंगे। व्हॉट्सएप ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मेटा के स्वामित्व वाले मंच ने कहा, 'यह फीचर पूरी दुनिया में चलाना शुरू कर दिया गया है और कुछ सप्ताह में यह सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा।' मंच ने कहा, 'आज, हम एक व्हॉट्सएप खाते को कई फोन पर एक साथ चलाने की सुविधा शुरू कर रहे हैं।' उपभोक्ता लंबे समय से इस फीचर की मांग कर रहे थे। इससे वे अपने फोन को चार अतिरिक्त उपकरणों से जोड़ सकेंगे, जैसे आप व्हॉट्सएप को वेब ब्राउजर, टैबलेट और डेस्कटॉप पर जोड़ते हैं।मंच ने बताया, व्हॉट्सएप खाते से जुड़ा प्रत्येक फोन सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता के निजी मैसेज, मीडिया और कॉल सिर्फ वह और उससे संपर्क करने वाला ही जान सके। व्हॉट्सएप ने एक बयान में कहा, 'अगर आपका मूल उपकरण लंबे समय से सक्रिय नहीं है तो हम आपके व्हॉट्सएप को अन्य सभी उपकरणों से स्वतः ही लॉग आउट कर देंगे।'

बदल गए हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत टैक्स-बेनेफिट

क्लेम करने के नए नियम

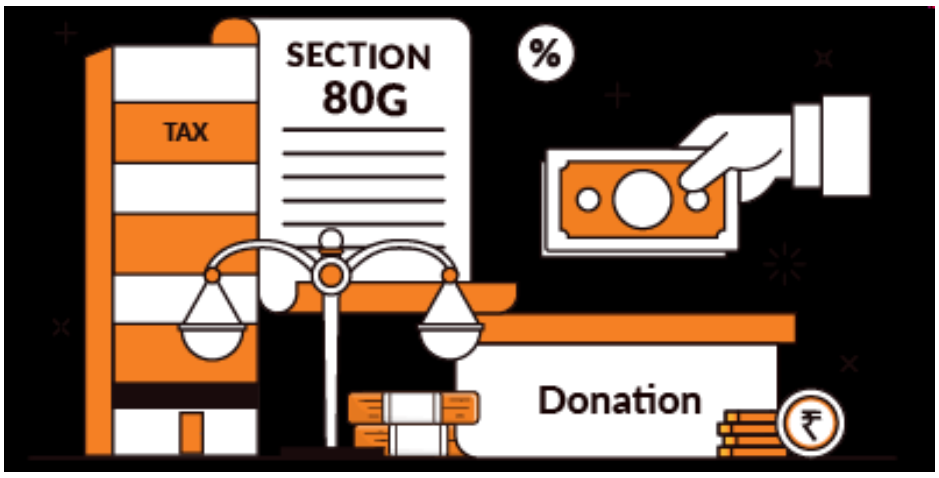

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने चैरिटी पर टैक्स बेनेफिट क्लेम करने के नियमों को सख्त बना दिया है। मान्यताप्राप्त चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या एनजीओ को दिए गए डोनेशन पर टैक्स बेनेफिट का दावा किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80G (Section 80G of Income Tax Act) के तहत यह टैक्स बेनेफिट मिलता है। अब इस सेक्शन के तहत टैक्स बेनेफिट का दावा करने के नियम को सरकार ने बदल दिया है। अब इसके लिए TDS जैसा सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इस सर्टिफिकेट को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड करना पड़ेगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

क्या है नया प्रावधान?

सेक्शन 80जी के नए प्रावधान के मुताबिक, डोनेशन सर्टिफिकेट को डोनेशन का प्रूफ माना जाएगा। इसे इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड करना होगा। पहले डोनेशन पर टैक्स बेनेफिट क्लेम करने के लिए इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह नियम फाइनेंशियल ईर 2020-21 तक लागू था। तब जिस संस्थान को डोनेशन किया जा रहा है, उसकी तरफ से जारी की गई रसीद की मदद से टैक्स बेनेफिट का क्लेम किया जा सकता था। उसके बाद सरकार ने इस नियम को बदल दिया । डोनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स बेनेफिट क्लेम करने सहित दूसरे तरह के फायदे उठाने के नियमों को ऑनलाइन कर दिया है। अब सेक्शन 80 जी के तहत डोनेशन पर टैक्स- बेनेफिट क्लेम करने के प्रोसेस को भी ऑनलाइन बनाया गया है। अब चैरिटेबल

इंस्टीट्यूशंस को मिले डोनेशन को टैक्सपेयर्स की तरफ किए जाने वाले क्लेम से मैच कराया जाता है। इसके लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या एनजीओ के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में मिले सभी डोनेशन का स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर डालना जरूरी है। इसके अलावा उसे चैरिटी करने वाले व्यक्ति को अलग से सर्टिफिकेट जारी करना जरूरी है।

31 मई से पहले डोनेशन स्टेटमेंट फाइल करना होगा

चैरिटी लेने वाले इंस्टीट्यूशन या एनजीओ को फॉर्म 10BD में स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल करना पड़ता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना जरूरी है। इसे हर फाइनेंशियल ईयर में 31 मई से पहले इंस्टीट्यूशन या एनजीओ के लिए स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन फाइल कर देना जरूरी है।

इसे हम एक उदाहरण की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप मान्यता प्राप्त एक संस्थान को 1 अगस्त, 2022 को 1 लाख रुपये का डोनेशन करते हैं। यह डोनेशन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में किया जाता है। डोनेशन पाने वाली कंपनी को इसका स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 31 मई, 2023 तक कर देना होगा। जब आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको डोनेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी तरफ से दी गई जानकारी को इंस्टीट्यूशन की तरफ से फाइल किए गए स्टेटमेंट ऑफ डोनेशन से मैच कराएगा। इसके मैच करने के बाद ही टैक्स बेनेफिट का आपके क्लेम को एप्रूवल मिलेगा।

करदाताओं के आवेदनों पर निश्चित समय-सीमा में हो उचित कार्रवाई: सीतारमण

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को करदाताओं के सभी आवेदनों पर निश्चित समय-सीमा के भीतर उचित कार्रवाई करने को कहा है। सीतारमण ने सीबीडीटी के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में यह बात कही। इस बैठक में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता और सीबीडीटी के सभी सदस्य शामिल हुए।

वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि वित्त मंत्री को यहां आयोजित इस समीक्षा बैठक में सीबीडीटी की ओर से कर आधार बढ़ाने को लेकर उठाये गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में व्यक्तिगत आयकर वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 2.94 फीसदी हो गया, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 2.11 फीसदी था। सीबीडीटी ने बताया कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से करदाताओं का आधार बढ़ा है। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संहिता पेश किए जाने से वित्त वर्ष 2021-22 में सूचित लेन-देन बढ़कर 144 करोड़ हो गया, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 70 करोड़ था। साथ ही टीडीएस काटने वालों की संख्या बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 9.2 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 2015-16 में 4.8 करोड़ थी। मंत्रालय के मुताबिक समीक्षा बैठक में करदाता आधार बढ़ाने के प्रयास, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित मामले और कुछ धाराओं के तहत छूट प्रदान करने को लेकर आयकर अधिनियम, 1961 समेत अन्य चीजों की भी समीक्षा की गई। वित्त मंत्री ने सीबीडीटी को प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों और उनके अनुपालन के बारे में करदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के अपने प्रयासों को विस्तार देने और इन्हें मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया।

EPFO ने अब तक नहीं हटाया हायर पेंशन से जुड़ा विवादास्पद नियम

नई दिल्ली। एजेंसी

केरल हाई कोर्ट ने हाल में ईपीएफओ (EPFO) को हायर पेंशन से जुड़ा एक अनिवार्य नियम को हटाने का अंतरिम आदेश दिया था। इस नियम के तहत हायर पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एप्लिकेंट को अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी पर आधारित पीएफ कंट्रीब्यूशन के लिए प्रायर परमिशन का प्रूफ जमा करना होगा। 12 अप्रैल को केरल हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को इस क्लौज को 10 दिन के भीतर एप्लिकेशन फॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने ईपीएफओ से कहा था कि वह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पूर्व सहमति का प्रमाण पत्र देने की जरूरत के बिना हायर कंट्रीब्यूशन का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए अपनी ऑनलाइन प्रणाली में प्रावधान करे। लेकिन दस दिन से अधिक वक्त गुजर जाने के बाद भी ईपीएफओ ने इस क्लौज को नहीं हटाया है। हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेडलाइन तीन मई को खत्म हो रही है। ऐसे में ईपीएफओ की ढिलाई से एप्लिकेंट्स कनफ्यूज हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे एप्लिकेशन कैसे जमा करें। साथ ही डिपॉजिट के तरीके को लेकर भी उनमें कन्फ्यूजन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कितना पैसा जमा करना होगा, कितना ब्याज होगा और पेंशन की गणना किस प्रकार होगी।

इस बीच ईपीएफओ ने अपने फील्ड ऑफिसर्स को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें बताया गया है कि सबमिट की गई एप्लिकेशंस की किस तरह जांच की जानी है। अगर कर्मचारी या एम्प्लॉयर की तरफ से कोई कमी है तो इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। एचआर एक्सपर्ट्स ने इस सर्कुलर का स्वागत किया है। लेकिन उनका कहना है कि इस सर्कुलर में कई चीजें साफ नहीं है। मसलन अगर एप्लिकेंट यूनिफाइड पोर्टल के जरिए एप्लिकेशन जमा करता है ते उसे सैलरी से जुड़ी जानकारी देने के लिए एम्प्लॉयर को कितना समय मिलेगा। इस बारे में ईपीएफओ के किसी भी सर्कुलर में स्पष्टता नहीं है।

किस बात को लेकर है कनफ्यूजन

इन मुद्दों पर कनफ्यूजन के कारण सब्सक्राइबर्स इस बात को लेकर पसोपेश में हैं कि उन्होंने हायर पेंशन का विकल्प चुनना चाहिए या नहीं। ईपीएफओ का कहना है कि बकाये की गणना तभी होगी जब जॉइंट एप्लिकेशन में एम्प्लॉयर द्वारा दी गई जानकारी का मिलान ईपीएफओ के डेटा से होगा। इसके बाद ही बकाया डिपॉजिट करने या इसे ट्रांसफर करने के बारे में ऑर्डर जारी होगा। अगर ईपीएफओ के डेटा और कर्मचारी तथा नियोक्ता के दिए गए डेटा में मिलान नहीं होता है तो इसे दुरुस्त करने के लिए एक महीने समय दिया जाएगा। ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों को आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला है जो एक सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए थे और ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए हकदार थे।

रोजमर्रा के कानूनी विषयों पर 1000 से अधिक वीडियो लेक्चर अपलोड करने वाले इंदौर के पंकज वाधवानी मध्य प्रदेश में प्रथम

यूट्यूब के माध्यम कानूनी जागरूकता फैला रहे हैं लॉ प्रोफेसर पंकज वाधवानी... रोजमर्रा के जीवन में आने वाली कानूनी दिक्कतों पर रोज एक वीडियो लेक्चर

इंदौर। इंदौर हाई कोर्ट अधिवक्ता और लो प्रोफेसर पंकज वाधवानी द्वारा लॉकडाउन से आम लोगों के हितों कि की रक्षा हेतु कानूनी जागरूकता संबंधी रोज एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क अपलोड करना प्रारंभ किया था , यह क्रम पिछले 32 महीनों से निरंतर चल रहा है और अभी तक 1000 से ज्यादा वीडियो लेक्चर रोजमर्रा के जीवन में आने वाली कानूनी दिक्कतों एवं उनके समाधान को लेकर जारी कर चुके हैं। अधिवक्ता पंकज वाधवानी का शुरू से ही ध्येय रहा है कि निःशुल्क कानूनी परामर्श प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए क्योंकि विधिक साक्षरता से आने वाली समस्याएं और विवाद स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं जो कि ना सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति के हित में होता है बल्कि यह समाज और राष्ट्र के हित में है।

वसीयत, बीमा क्लेम, संपत्ति विवादों पर देशभर से आते हैं फोन कॉल

लॉ लेक्चर और पंकज वाधवानी द्वारा आम व्यक्तियों को आए दिन जूझने वाली समस्याओं के विषयों पर अपलोड किए गए वीडियो में जैसे वसीयत ड्राफ्ट करते समय किन बातों का ख्याल रखें , मेडिक्लेम तथा इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें, खाली पड़े प्लॉट पर कोई व्यक्ति अवैधानिक कब्जा कर ले तो क्या किया जाए, पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं की जाती है, तो उसके लिए क्या कानूनी उपचार है इत्यादि विषयों पर देश के अलग-अलग राज्यों और शहरों से फोन कॉल आते हैं जिस पर वाधवानी उन्हें निशुल्क कानूनी परामर्श उपलब्ध कराते हैं। पंकज वाधवानी द्वारा लो इजी के नाम से यूट्यूब चैनल 23 अगस्त 2020 से प्रारंभ किया था जो कि भारत में ही नहीं पाकिस्तान, नेपाल, यूएई, अमेरिका इत्यादि देशों में भी देखा जा रहा है।

32 महीनों में 67000 से ज्यादा फॉलोवर

5 मिनट से 8 मिनट के छोटे-छोटे वीडियो लेक्चरर्स के माध्यम से इंदौर के वकील पंकज वाधवानी के पिछले 32 महीनों में 67000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं

आम आदमी को महंगाई से नहीं मिलेगी राहत

जेब पर और बढ़ेगा बोझ, वित्त मंत्रालय ने दिए ये बड़े संकेत

नई दिल्ली। एजेंसी

थोक और महंगाई दर में बेशक गिरावट का रुख जारी है, मगर महंगाई बढ़ने का रिस्क बना हुआ है। यह बात वित्त मंत्रालय की मार्च महीने के मंथली इकॉनमिक रीव्यू से सामने आई है। इसमें मंत्रालय ने कहा है कि महंगाई से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कम कृषि उत्पादन, उच्च कीमतों और ग्लोबल इकॉनमी में सुस्ती का प्रभाव भारत की इकॉनमी पर पड़ सकता है। रीव्यू यानी समीक्षा में कहा गया है कि बढ़ती महंगाई को थामने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी में जो कड़ा रुख अपनाया गया, उसने ग्रोथ की प्रक्रिया को कमजोर कर दिया है। इसके अलावा फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े जंग का भार तीन वर्षों तक आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने की आशंका है।

भारत की इकॉनमी मजबूत

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत की इकॉनमी में चालू वित्त वर्ष के लिए 6.5ङ्ग की उ्रङ्ग ग्रोथ का अनुमान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के अनुमानों के अनुरूप है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इकॉनमी ग्रोथ को प्रभावित कर सकती हैं। मसलन अल नीनो से सूखे जैसे हालात बन सकते हैं। इससे कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है। कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा भू राजनीतिक परिवर्तन और ग्लोबल इकॉनमी में अस्थिरता जैसे संभावित रिस्क को देखते हुए सतर्क रहना रहने की जरूरत है।

बेशक कोरोना महामारी और उक्त दूसरी चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था 2022-23 में मजबूत रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की इकॉनमी में मजबूती देखी जा रही है, इसके सात फीसदी की दर से बढ़ने करने का अनुमान है जो दूसरी प्रमुख इकॉनमी की तुलना में अधिक है। भारत की इकॉनमी में मजबूती का यह संकेत है कि चालू खाता घाटा कम हो रहा है, विदेशी पूंजी की आवक से विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हो रही है।

फिलहाल महंगाई काबू में

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि साल 2021-22 में पूरे वर्ष के लिए रिटेल महंगाई दर 5.5% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 6.7% पर पहुंच गई। यह 2022-23 की दूसरी तिमाही में 6.1% पर ही रही, जो पहली छमाही में 7.2% था। अंतरराष्ट्रीय जिंसों के दामों में नरमी, सरकार के त्वरित कदमों और RBI की सख्त मॉनिटरी पॉलिसी ने घरेलू स्तर पर महंगाई को काबू करने में मदद दी।

बैंकिंग सिस्टम मज़बूत

वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण होने वाले तनाव से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत है। RBI ने स्थितियों को देखते हुए जिस तरह से कदम उठाए हैं, वह उसकी बहुआयामी प्रकृति को दिखाता है। भारतीय बैंकों के बैलेंस शीट में सुधार हुआ है। ब्याज दरों में बदलाव को भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने जिस रणनीतिक तरीके से अपनाया, उससे भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए अच्छा संकेत मिलता है। यह भारत में सिलिकॉन वैली बैंक जैसी घटना होने संभावना को काफी कम कर देता है। हाल ही अमेरिका और यूरोप में कई बैंक वित्तीय रूप से डूब गये। समीक्षा में कहा गया है कि RBI और सरकार की ओर से हाल के वर्षों में किए गए उपायों ने बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता दी है, साथ ही रिस्क झेलने की क्षमता में सुधार किया है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र पर निगरानी बढ़ाई है और इसके दायरे में आने वाले संस्थान बढ़े हैं। बैंकों पर दबाव का परीक्षण भी समय-समय पर किया जाता है। समीक्षा के मुताबिक जमा की तेजी से निकासी होने की आशंका नहीं है क्योंकि 63% जमा परिवारों की ओर से किए जाते हैं जो निकासी जल्द नहीं करते। इन सब कारकों की वजह से भारत के बैंक अमेरिका और यूरोप के बैंकों से अलग हैं।

द इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट

कारोबारी माहौल में सिंगापुर को टक्कर दे रहा भारत, एक साल में हुए बड़े सुधार

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए पिछले एक साल में बड़े सुधार किए हैं। इस मामले में अब वह सिंगापुर को टक्कर दे रहा है। प्रमुख बड़े सुधारों की वजह से विदेशी कंपनियों (विनिर्माता) के लिए भारत आकर्षक गंतव्य के रूप में सामने आ रहा है। द इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) की ओर से हाल ही में जारी वैश्विक कारोबारी माहौल रैंकिंग (बीईआर) में भारत 6 पायदान ऊपर आ गया है। वहीं, 17 एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में 14वें से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष पर काबिज है। यह रैंकिंग उन देशों को दी जाती है, जहां अगले पांच साल में कारोबारी माहौल पूरी दुनिया में सबसे अच्छा होगा।

वैश्विक कारोबारी माहौल रैंकिंग में 91 संकेतकों के आधार पर 82 देशों में कारोबारी माहौल को लेकर आकर्षण का मापन किया जाता है। 2023 की दूसरी तिमाही के लिए जारी इस रैंकिंग से पता चलता है कि नीतिगत सुधारों की वजह से भारत में कारोबार करना पहले के मुकाबले आसान हो गया है। इसके साथ ही, बुनियादी ढांचा, कराधान और कारोबार को लेकर नियमन में सुधार से निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

इन वजहों से रैंकिंग में सुधार

इकोनॉमिस्ट ग्रुप के अनुसंधान विभाग ने कहा कि कारोबारी माहौल के मोर्चे पर भारत के बेहतर प्रदर्शन के पीछे विदेशी व्यापार, विनिमय नियंत्रण, बुनियादी ढांचे पर जोर और तकनीकी को अपनाने में तत्परता अहम कारक हैं। इसके अलावा, मजबूत एवं स्थिर अर्थव्यवस्था, व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम, श्रमिकों की बेहतर

आपूर्ति से भी भारत में कारोबार करना आसान हुआ है।

विनिर्माण में निवेश के मोर्चे पर चिंता

ईआईयू ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत विनिर्माण में निवेश को लेकर ऐतिहासिक रूप से संघर्ष कर रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य उभरते बाजारों से उसे कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। इसके अलावा, अत्यधिक लालफीताशाही और संरक्षणवादी रवैया निवेशकों के लिए चुनौती बना रहेगा। हालांकि, भारत के पास अपने विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार का सुनहरा अवसर है। इससे न सिर्फ आर्थिक विकास व निर्यात को गति मिलेगी बल्कि जीडीपी में हिस्सेदारी भी बढ़ेगी, जो अभी 20ङ्ग से कम है।

चीन पर अधिक निर्भरता हमारे लिए मौका

ईआईयू ने रिपोर्ट में कहा है कि एपल समेत कई बड़ी विदेशी कंपनियां आपूर्ति को लेकर चीन पर अधिक निर्भरता और उसकी 'चाइन प्लस वन' नीति से सावधान हो गई हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। चीन की नीतियों की वजह से एपल चीनी कारखानों पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए भारत में उत्पादन बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है।

ब्लूमबर्ग ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एपल की विनिर्माता कंपनी फॉक्सकॉन भारत में विनिर्माण बढ़ाना चाह रही है। वह बंगलूरू के पास फैक्टरी लगाने के लिए 70 करोड़ डॉलर की निवेश की योजना बना रही है। इससे एक लाख नौकरियों भी पैदा होंगी। भारतीय अधिकारियों का कहना है, एपल अपने कुल उत्पादन का 25 फीसदी भारत में करना चाहती है। अभी यह करीब 5-7 फीसदी है।

सैमसंग भी करेगी निवेश : सैमसंग ने मार्च में कहा था कि वह उत्पादन को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नोएडा के मोबाइल फोन प्लांट में स्मार्ट विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने में निवेश करेगी। कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का अनुमान है कि 2026 में भारत में एक अरब स्मार्टफोन यूजर्स होंगे।

क्रिकेट से प्रेरित मेनू और मज़ेदार एंगेजमेंट्स के साथ सोशल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत का पसंदीदा हैंगआउट, सोशल (SOCIAL) भारत के शहरों में क्ष्दूसरास्टेडियम का अनुभव देकर इस वर्ष के क्रिकेट सीज़न के लिए लोगों का उत्साह बढ़ा रहा है। सोशल, खेल और इसके प्रति भावना को दर्शाने के लिए, दिलचस्प क्रिकेट थीम ड्रिंक्स और इट्स लेकर आ रहा है, जिसके चटखारे आप अपने शहर में रहकर मैच टाइम में ले सकते हैं। इस प्रकार, आप 11 अप्रैल से लेकर 28 मई तक अपने दूसरास्टेडियम में प्लेयर्स की जीत को सेलिब्रेट कर सकते हैं।

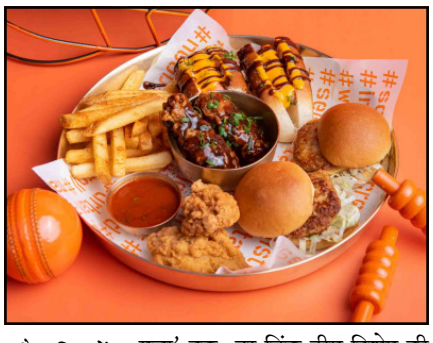

यह क्रिकेट सीज़न बेहद शानदार है, जिसमें सोशल, युवा खेल प्रतिभाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए सहयोग कर रहा है। क्रिकेट के सुपरस्टार्स- तिलक वर्मा, ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एसोसिएशन, दूसरास्टेडियम कैंपेन का मुख्य आकर्षण है। तीनों ही खिलाड़ी अपनी शानदार परफॉर्मेंसेस से हर किसी को अपना बना चुके हैं। जहाँ एक तरफ सोशल, चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का ऑफिशियल हाउस है, वहीं दिल्ली एनसीआर आउटलेट्स में दिल्ली कैपिटल्स के लिए विशेष अड्डा है।

नए स्टैड-यम मेनू में विशेष इट्स (#eats) और ड्रिंक्स (#drnks) को शामिल किया गया है, जो सभी 10 टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंजाब समर्थकों के लिए 'किंग्स एलएलआईआईटी' से लेकर दिल्ली गैंग के लिए 'रोर मचा' तक, हर ड्रिंक टीम विशेष की भावना से ओतप्रोत है और सामाजिक व स्थानीय संस्कृति का प्रतिबिंब है। मूड सेट कर देने वाले इट्स के बिना मैच का लगभग हर अनुभव अधूरा है। सोशल के हिटमैन्स चिकन प्लैटर, मज्जा मा टाइटन्स चकना, व्हिसल पोडुचिली चिकन जैसे मुँह में पानी ला देने वाले व्यंजन देश भर में मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, इंदौर, देहरादून और चंडीगढ़ में दूसरास्टेडियम के अनुभव को बढ़ाने का वादा करते हैं।

गंगा में नहाने और जल लाने का भी होता है नियम, अनदेखी करने से लगता है महापाप

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

सनातन परंपरा में गंगा नदी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है क्योंकि इसका अमृत जल जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है. जिस गंगा में आस्था की डुबकी लगाते ही व्यक्ति के पूर्व और इस जन्म से जुड़े सारे दोष और पाप दूर हो जाते हैं, उसके प्राकट्य से जुड़ा गंगा सप्तमी पर्व हर साल वैशाख मास के शुक्लपक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार भागीरथी कहलाने वाली मां गंगा से जुड़ा यह पर्व 27 अप्रैल को मनाया जाएगा. यदि आप इस महापर्व पर गंगा तट पर जाकर स्नान, ध्यान और दान करने की सोच रहे हैं तो आपको नीचे बताए गये नियमों को जरूर ख्याल रखना चाहिए.

- गंगा जयंती के पावन पर्व पर यदि आप किसी गंगा तीर्थ पर जाएं तो वहां पर गंगा नदी के जल में हमेशा चप्पल और जूते उतारकर ही प्रवेश करना चाहिए.
- गंगा सप्तमी के पावन पर्व पर यदि आप गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं तो भूलकर भी वहां पर अपने न तो कपड़े धोएं और निचोड़ें और न ही नहाते समय साबुन का प्रयोग करना चाहिए.
- गंगा सप्तमी के दिन गंगा तीर्थ पर जाकर भूलकर भी न तो किसी के प्रति बुरा भाव लाना चाहिए और न ही किसी को बुरा-भला नहीं कहना चाहिए.
- कई बार गंगा तीर्थ पर जाते समय अपने घर में पूजा-पाठ में प्रयोग लाई गई सामग्री का कूड़ा-कचरा फेंकने के लिए ले जाते हैं. गंगा नदी में कभी भूल कर भी पूजा अथवा अन्य प्रकार कचरा नहीं फेंकना चाहिए.
- सनातन परंपरा में न सिर्फ गंगा स्नान और पूजन करने के लिए नियम बताए गये हैं बल्कि गंगा जल को घर में लाने और उसे रखने के लिए का भी तरीका बताया गया है. यदि आप प्लास्टिक के पात्र में गंगाजल लेकर घर आते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है. हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा जल को किसी धातु से बने पात्र में रखने से उसकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहती है.
- हिंदू मान्यता के अनुसार घर में गंगा जल जाने के साथ उसे रखने के लिए भी नियम बताया गया है. घर में गंगा जल हमेशा घर के ईशान कोण में पवित्र स्थान पर रखना चाहिए और इसे कभी भी जूठे हाथों या फिर अपवित्र होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए.
- यदि आप गंगा सप्तमी वाले दिन गंगा तट पर जाकर इस पावन पर्व का पुण्यफल पाने के लिए किसी विशेष चीज का दान करना चाहते हैं तो आपको उसे किसी जरूरतमंद या फिर कहें सुयोग्य व्यक्ति को ही इसे देना चाहिए. साथ ही साथ ऐसा करते समय आपको भूलकर भी अभिमान नहीं करना चाहिए. मान्यता है कि अभिमान या फिर प्रदर्शन करते हुए जो भी चीज का दान किया जाता है, उसका पुण्यफल नहीं मिलता है.

गंगा सप्तमी पर बन रहे शुभ संयोग, गंगा स्नान के इन नियमों का रखें ध्यान

श्री रघुनंदन जी
9009369396
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट

इस साल 27 अप्रैल 2023 को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। गंगा सप्तमी के दिन दान-पुण्य, पूजा-पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन मां गंगा की उत्पत्ति हुई थी। सनातन परंपरा में गंगा नदी का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है क्योंकि इसका अमृत जल जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के साथ जुड़ा रहता है। मान्यताओं के अनुसार, गंगा सप्तमी के दिन पूजा अर्चना करने से व दान-पुण्य करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है और जातक के हर पाप नष्ट हो जाते हैं।

बन रहे हैं शुभ योग

इस साल 27 अप्रैल 2023 को गंगा सप्तमी के दिन तीन शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि और गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा और अमृत सिद्धि योग सुबह 7 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। इसके साथ ही गुरु पुष्य योग सुबह 7 बजे से अगले दिन 28 अप्रैल को सुबह 05 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। यदि आप इस महापर्व पर गंगा तट पर जाकर स्नान, ध्यान और दान करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का जरूर ख्याल रखना चाहिए।

गंगा में स्नान के नियम

गंगा नदी या किसी भी पवित्र तीर्थ पर जाएं तो नदी के जल में प्रवेश करने से पहले चप्पल-जूते अवश्य उतार कर जल को स्पर्श करें।

गंगा जी में स्नान करने के बाद वहां पर अपने न तो कपड़े धोएं और निचोड़ें। साथ ही नहाते समय साबुन का प्रयोग भी ना करें।

गंगा नदी में अपने घर में पूजा-पाठ में प्रयोग लाई गई सामग्री का कूड़ा-कचरा कभी नहीं फेंकना चाहिए

अगर स्नान के बाद गंगा जल को घर लाना चाहें, तो किसी धातु के पात्र में लाएं। गंगा जल को किसी धातु के पात्र में रखने से उसकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहती है।

गंगा जल को कभी भी जूठे हाथों या फिर अपवित्र होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए।

गंगा तट पर दान का भी बड़ा महत्व है। लेकिन दान किसी जरुरतमंद या सुयोग्य को ही करें और दान का अभिमान बिल्कुल ना करें। अन्यथा आपको इसका पुण्यफल नहीं मिलेगा।

मई महीने में 13 दिन गूंजेगी शहनाई

सनातन धर्म में विवाह को एक मांगलिक कार्य माना जाता है। इस शुभ कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त बहुत महत्व रखता है। खरमास की वजह से बंद हुई शहनाई एक बार फिर गूंजने के लिए तैयार हैं। ऐसा माना जाता है कि अशुभ मुहूर्त में किए गए विवाह का अक्सर जोड़े पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शादी विवाह को शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है । यह परंपरा हमारे हिन्दू रीति रिवाज में बहुत ही शुभ माना गया है। विवाह से पहले वर वधु की कुंडलियों को देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल में कुल 4 अबूझ मुहूर्त होते हैं। इनमें आखा तीज, देवउठनी एकादशी, बसंत पंचमी और भड़ली नवमी। यानी इन चार मौकों पर मुहूर्त न होते हुए भी विवाह किए जा सकते हैं। बता दें कि मई महीने में कुल 13 दिन विवाह के शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। आइये जानते हैं मई माह में विवाह की तारीखें।

मई महीने में विवाह का शुभ मुहूर्त

8 मई 2023 (सोमवार), मुहूर्त- रात 12:49 बजे से सुबह 05:35 बजे तक, 9 मई 2023

9 मई 2023 (मंगलवार), मुहूर्त- सुबह 05:35 बजे से शाम 05:45 बजे तक, नक्षत्र- मुला

10 मई 2023 (बुधवार), मुहूर्त- शाम 04:12 बजे से सुबह 05:33 बजे तक, 11 मई 2023

11 मई 2023 (गुरुवार), मुहूर्त- सुबह 05:33 बजे से सुबह 11:27 बजे तक

15 मई 2023 (सोमवार), मुहूर्त- सुबह 01:30 बजे से सुबह 05:30 बजे तक, 16 मई 2023

16 मई 2023 (मंगलवार), मुहूर्त- सुबह 05:30 बजे से रात 01:48 बजे तक, 17 मई 2023

20 मई 2023 (शनिवार), मुहूर्त- शाम 05:18 बजे से सुबह 05:27 बजे तक, 21 मई 2023

21 मई 2023 (रविवार), मुहूर्त- सुबह 05:27 बजे से सुबह 05:27 बजे तक, 22 मई 2023

22 मई 2023 (सोमवार), मुहूर्त- सुबह 05:27 बजे से सुबह 10:37 बजे तक

27 मई 2023 (शनिवार), मुहूर्त- रात 08:51 बजे से रात 11:43 बजे तक

29 मई 2023 (सोमवार), मुहूर्त- रात 09:01 बजे से सुबह 05:24 बजे तक, 30 मई 2023

30 मई 2023 (मंगलवार), मुहूर्त- सुबह 05:24 बजे से रात 08:55 बजे तक

कालसर्प दोष से पीड़ित जातक को धारण करना चाहिए गोमेद

वैदिक ज्योतिष के अनुसार गोमेद रत्न का संबंध राहु ग्रह से होता है। यह सामान्यतः शहद के रंग जैसा होता है और गहरे भूरे या लाल रंग की तरह प्रतीत होता है। गोमेद रत्न में क्रूर और शक्तिशाली राहु ग्रह की ऊर्जा होती है। राहु का कलयुग में अधिक महत्व और प्रभाव है। इस वजह से गोमेद एक प्रभावशाली रत्न है, जो राहु ग्रह के दोषों को दूर करता है। गोमेद को धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मन में सकारात?मक विचार पैदा होते हैं। कहते हैं गोमेद को धारण करने से एकाग्रता बढ़ती है और अनिद्रा की समस्या से मुक्ति मिलती है। यदि प्रोफेशनल?स गोमेद को धारण करते हैं तो उनके सभी अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे होते हैं। आइये जानते हैं गोमेद रत्न के नुकसान और फायदे क्या हैं।

फायदे- गोमेद रत्न कालसर्प दोष से पीड़ित जातकों के लिए लाभदायक होता है। इस धारण करने से काल सर्प दोष से होने वाले बुरे प्रभावों से बचाव होता है। ■गोमेद राजनीति, जन संपर्क, दलाली से जुड़े व्यवसाय और प्रबंधन से संबंधित कार्य करने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद बताया गया है।■गोमेद के प्रभाव से शक्ति, सफलता और धन की प्राप्ति होती है। ■यदि जन्म कुंडली में राहु की महादशा और अंतर्दशा के समय कोई व्यक्ति गोमेद रत्न पहनता है तो राहु ग्रह के बुरे प्रभावों से उसकी रक्षा होती है। ■ऐसे लोग जो पेट संबंधी विकार, सुस्त उपापचय से परेशान हैं उनके लिए गोमेद धारण करना फायदेमंद होता है। क्योंकि यह स्वास्थ्य और शक्ति को भी दर्शाता है। ■गोमेद के प्रभाव से विरोधियों पर विजय मिलती है और मन में आने वाले निराशावादी विचार भी दूर होते हैं।

नुकसान- ऐसी मान्यता है कि महिलाएं अगर कम चमकीला गोमेद पहनती हैं तो उसके बुरे प्रभाव सामने आते हैं। ■यह भी माना जाता है कि कम चमकीला गोमेद धारण करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है। ■यदि कोई व्यक्ति बहुरंग वाला गोमेद रत्न धारण करता है, तो उसे स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ■वह गोमेद रत्न जिस पर गहरे दाग होते हैं, यह दुर्भाग्य या दुर्घटना की संभावना को दर्शाता है।

जियो यूजर्स ने एक महीने में उड़ा डाला 10 अरब जीबी डेटा

दो साल में 1.8 गुना बढ़ी खपत

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने इतिहास रच दिया है। जियो यूजर्स ने एक महीने में 10 एक्साबाइट यानी 10 अरब जीबी डेटा का इस्तेमाल कर डाला। यह आंकड़ा कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2016 में जब रिलायंस जियो ने टेलिकॉम सेक्टर में एंट्री मारी थी, उस वक्त पूरे देश के सभी उपलब्ध नेटवर्क्स पर डेटा खपत सालाना मात्र 4.6 एक्साबाइट थी। भारत में पहली बार किसी टेलिकॉम कंपनी के नेटवर्क पर एक महीने में 10 एक्साबाइट डेटा की खपत हुई है। मार्च तिमाही में जियो नेटवर्क पर डेटा की खपत का आंकड़ा 30.3 एक्साबाइट था। रिलायंस जियो ने अपने तिमाही नतीजों में इसका खुलासा किया। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद अपने मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। इस दौरान कंपनी को रेकॉर्ड मुनाफा हुआ है।

जियो ट्रू 5जी रोलआउट ने डेटा की बढ़ती खपत में अहम भूमिका निभाई। जियो यूजर अब हर महीने औसतन 23.1 जीबी डेटा खर्च कर रहा है। जो दो साल पहले तक मात्र 13.3 जीबी प्रतिमाह था। यानी प्रत्येक जियो यूजर दो साल पहले की तुलना में करीब 10 जीबी प्रतिमाह अधिक डेटा की खपत कर रहा है। जियो नेटवर्क पर डेटा खपत का यह औसत, टेलीकॉम इंडस्ट्री की औसत से कहीं अधिक है। तिमाही रिजल्ट्स के मुताबिक जियो ने मार्च 2023 तक 60 हजार साइट्स पर 3.5 लाख से अधिक 5जी सेल्स लगा लिए थे। देश भर में 2,300 से अधिक शहर और कस्बे 5जी की कवरेज में आ गए हैं और जियो यूजर्स भारी संख्या में 5जी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं।

बढ़ गया पर यूजर रेवेन्यू

कंपनी का दावा है कि जियो बेहद तेजी से 5जी का रोलआउट कर रहा है। दुनिया भर में 5जी के रोलआउट की ऐसी कोई मिसाल नही है। कंपनी 2023 के अंत तक पूरे देश में 5जी कवरेज पहुंचाना चाहती है। 5जी रोलआउट के साथ-साथ कंपनी एयरफाइबर के लॉन्च की तैयारियां भी कर रही है। जियो ने बताया कि अगले कुछ महीनों में इसका लॉन्च संभव है। रिलायंस जियो का लक्ष्य 10 करोड़ घरों को फाइबर और एयरफाइबर से जोड़ने का है। रिजल्ट्स में कुछ और महत्वपूर्ण बाते भी निकल कर आईं, जैसे जियो का औसत राजस्व प्रति यूजर प्रतिमाह (ARPU) बढ़कर 178.8 रुपये हो गया है। कंपनी के नेटवर्क पर हर दिन यूजर्स 1,459 करोड़ मिनट बातचीत (वॉयस कालिंग) कर रहे हैं। जियो नेटवर्क से जुड़े हर फोन पर करीब 1,003 मिनट हर महीने कॉलिंग हो रही है।

LED Expo के सिल्वर जुबली एडिशन में स्मार्ट होम्स और लाइटिंग नॉलेज सेशन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

जब लाइटिंग इंडस्ट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रदर्शित करने की बात आती है तो LED Expo एक ट्रेंड सेटर रहा है। 200 से अधिक एक्जीबिटर और नए जमाने के प्रोडक्ट्स की भरमार के साथ ट्रेड शो वर्सेटाइल लाइटिंग सॉल्यूशन के साथ बेहद रोमांचक होने का वादा करता है। LED Expo मुंबई 2023 बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, नेस्को, गोरेगांव में 11 से 13 मई 2023 तक एलईडी इंडस्ट्री का स्वागत करेगा। भारत ने संस्थागत और घरेलू दोनों स्तरों पर बड़े पैमाने पर एलईडी अपनाने और सस्टेनेबल लाइटिंग के प्रसार में बड़ी सफलता देखी है। हालांकि, भारत में एलईडी लाइटिंग को और अधिक अपनाने के लिए अभी भी काफी संभावनाएं मौजूद हैं और LED Expo भारत में तैयार लाइटिंग प्रोडक्ट्स, लाइटिंग कंट्रोल और कम्पोनेंट की कंप्लीट वैल्यू चेन को प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद प्लेटफार्म बना हुआ है। एक्सपो, जो कम्पोनेंट, एसेसरीज और मशीनरी शो के रूप में शुरू हुआ था, आज एलईडी और लाइटिंग इंडस्ट्री की पूरी रेंज को प्रदर्शित करता है, जिसमें शो में तैयार लाइटिंग प्रोडक्ट भी शामिल हैं। 2009 में महज 1,200 वर्ग मीटर में फैले शो से लेकर इस साल 10,881 वर्ग मीटर तक फैले मेले में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत और विदेशों से 200 से अधिक एक्जीबिटर के साथ LED expo का यह 25वां एडिशन लाइटिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे इफेक्टिव शो में से एक होने का वादा करता है।

नेक्सस इंदौर सेंट्रल मॉल ने मनाया अर्थ डे

पौधे लगाए और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

बेहद खास अनुभव देने और खानपान की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लोकप्रिय नेक्सस इंदौर सेंट्रल ने अर्थ डे के मौके पर अपने आगंतुकों को ऑर्गेनिक खेती से परिचित कराया। नेक्सस इंदौर सेंट्रल शहर का एकमात्र ऐसा मॉल है जिसने अपने टैरेस पर खेती शुरु की है और जो पर्यावरण के हित में सक्रिय है। अर्थ डे पर की गई इस गतिविधि का उद्देश्य था नगरवासियों को ऑर्गेनिक कृषि के बारे में जागरुक करना। इस प्रकार मॉल में आने वाले लोग पर्यावरण की भलाई में योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर ट्रैज़र आईलैंड और नेक्सस इंदौर सेंट्रल मॉल के सेंटर डायरेक्टर श्री रजत भार्गव ने कहा, ''इस विशिष्ट पहल को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। नेक्सस में हम हमेशा अपनी धरती और पर्यावरण की रक्षा हेतु किए जा रहे प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम इस बारे में बहुत सकारात्मक हैं कि हमारे ग्राहक भी इस विशिष्ट अनुभव #GrowYourHappyness का हिस्सा बनेंगे।

ईज़मायट्रिप ने ईज़ी समर सेल से तपती गर्मी में राहत दी

फ्लाइट्स, होटल्स, आदि पर डिस्काउंट्स

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रैवेल टेक प्लेटफॉर्म में से एक EaseMyTrip.com अपनी ईज़ी समर सेल को लॉन्च किया है, जिसमें यात्रियों के लिए खासकर गर्मी की छुट्टियों के लिये तैयार किये गये ऑफर्स हैं। ट्रैवेल सेल्स और डिस्काउंट्स की यह शानदार पेशकश 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2023 तक एक्टिव रहेगी। ग्राहक और यात्रा करने के शौकीन लोग ईज़मायट्रिप की वेबसाइट तथा ऐप पर सेल की अवधि के दौरान बुक किये गये फ्लाइट्स, होटल्स, बसेस, कैब्स, क्रूज़ेस और हॉलीडे पैकेजेस पर बड़ी छूट वाले ऑफर्स का फायदा ले सकते हैं।

ग्राहक ईज़मायट्रिप के भरोसेमंद हॉलीडे पैकेज भी ले सकते हैं, जिनके दाम सिर्फ 15,999 रूपये से शुरू हैं। समुद्र प्रेमियों के लिये शानदार क्रूज़ पैकेज 53,999 रूपये से शुरू होकर उपलब्ध हैं। छूट पाने के लिये यूजर्स अपने पसंदीदा गंतव्य के लिये फ्लाइट, होटल, बस, कैब, क्रूज़ या हॉलीडेज बुक कर सकते हैं और कूपन कोड EMTSUMMER का इस्तेमाल कर पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, अपनी बुकिंग्स के लिये आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड और एयू क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले ग्राहक 25 से 27 अप्रैल, 2023 तक अतिरिक्त छूट पा सकेंगे। सेल के इस सीजन को एक और आयाम देते हुए, सेल की अवधि के दौरान होने वाले हर ट्रांजैक्शन पर पैंटालून्स, जेबीएल, नैशर माइल्स और आईजीपी जैसे ब्राण्ड पार्टनर्स के एक चुनिंदा समूह से गिफ्ट वाउचर्स पाने का मौका मिलेगा। ईज़मायट्रिप के ब्राण्ड पार्टनर्स से यह खास वाउचर्स पाने के लिये ग्राहकों को ईज़मायट्रिप का ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम हैण्डल फॉलो करना है और ईज़ी समर सेल में शामिल होना है।

ईज़मायट्रिप के सह-संस्थापक रिकांत पिट्टी ने कहा, 'तपती गर्मी से भारत में यात्रा का उत्साह फीका नहीं पड़ना चाहिये। ईज़मायट्रिप में हम समझते हैं कि यात्रा का मतलब किसी जगह के इतिहास, संस्कृति और परंपरा पर शिक्षित होने से है और हम चाहते हैं कि इस गर्मी हर भारतीय यात्रा करे और देश के एक नये हिस्से को जाने। इसे संभव बनाने के लिये हम आपकी यात्रा सम्बंधी जरूरतों के हर पहलू पर भारी-भरकम डिस्काउंट दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक ईज़मायट्रिप पर खास ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा लेते हुए हमारे साथ टिकट बुक करेंगे।'

रियलमी ने 33W चार्जिंग और 64MP AI कैमरा के साथ नेक्स्ट-जनरेशन चार्जिंग लीडर नार्ज़ो N55 का अनावरण किया

मूल्य 10,999 रुपये से शुरू

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत में सबसे भरोसेमंद टेक्नोलॉजी ब्रांड, रियलमी ने नार्ज़ो N सीरीज़ में अब तक की अपनी पहली बेहतरीन पेशकश का अनावरण किया। रियलमी नार्ज़ो N55 अमेज़ॉन स्पेशल स्मार्टफोन है जिसमें इतनी कीमत में फ्लैगशिप स्तर के सेंसर के साथ 64MP का कैमरा और 33W चार्जिंग है। इसमें मिनी कैप्सूल भी है जो तीन आवश्यक विशेषताएं प्रदान करता है: चार्ज नोटिफिकेशन, डेटा यूसेज नोटिफिकेशन और स्टेप नोटिफिकेशन। नार्ज़ो N-सीरीज़ में स्टाईल एवं यूटिलिटी के साथ अत्याधुनिक फीचर्स, आधुनिक प्रिज़्म एस्थेटिक्स के साथ स्टाईलिश डिज़ाईन और शक्तिशाली प्रदर्शन जैसी खूबियाँ हैं। 'N' विस्तृत, अद्वितीय और असीमित संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। यह उन लोगों पर केंद्रित है, जो दूसरों द्वारा परिभाषित होने से इंकार कर देते हैं, और जिनकी अद्वितीय रुचियाँ, महत्वाकांक्षाएं, और आकांक्षाएं हैं। रियलमी नार्ज़ो जैन-ज़ी को अगली जनरेशन की डिवाईसेज़ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अमेज़ॉन के साथ शॉपिंग का बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है।

नार्ज़ो सबसे स्टाईलिश एंट्री लेवल ऑल-राउंडर स्मार्टफोन श्रेणी है, जो यूज़र्स को अतुलनीय अनुभव प्रदान करने के लिए बनाई गई है। भारत में इसके 12.3 मिलियन यूज़र्स हैं। नार्ज़ो N सीरीज़ के साथ रियलमी का उद्देश्य युवा पीढ़ी के लिए अगली जनरेशन के स्मार्टफोन बनाना है। रियलमी नार्ज़ो N55 33W की सुपरवूक चार्जिंग के साथ फास्ट चार्जिंग आम जनसमूह तक पहुँचा रहा है। इसकी मदद से स्मार्टफोन केवल 29 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है। रियलमी नार्ज़ो N55 में 64MP का AI कैमरा है, जिससे यूज़र्स को अपनी पूरी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। साथ ही इसमें 8MP का सेल्फी कैमरा और अनेक फोटोग्राफी फंक्शंस हैं, जिनमें एक्सक्लुसिव स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड और नाईट मोड के साथ कई दिलचस्प फोटोग्राफी के विकल्प शामिल हैं। रियलमी नार्ज़ो N55 के साथ रियलमी यूज़र्स को मिनी ड्रॉप स्क्रीन की बजाय पंच होल स्क्रीन का बेहतर अनुभव प्रदान कर रहा है और साथ ही 90 Hz. का रिफ्रेश रेट पेश कर रहा है। इस फोन में मीडियाटेक हेलियो उ88 चिपसेट लगा है। नार्ज़ो N55 विशाल स्टोरेज प्रदान करता है और सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ डाईनैमिक रैम के साथ आता है, जो 12GB डाईनैमिक रैम तक अपग्रेड हो सकती है।

एमएसडीई और एमओई G20 एडडब्ल्यूजी -फ्यूचर ऑफ वर्क के तहत प्रदर्शनी का आयोजन

भुवनेश्वर। एजेंसी

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और शिक्षा मंत्रालय (एमओई) जी20 की अध्यक्षता में 23 से 28 अप्रैल तक सीएसआईआर-इन्स्टीट्यूट ऑफ़ मिनरल्स एंड मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी (आईएमएमटी), भुवनेश्वर, ओडिशा के तीसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप (एडडब्ल्यूजी) की मीटिंग के दौरान भविष्य की कार्य प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत ने हर स्तर पर टेक इनेबल्ड लर्निंग को अधिक गुणात्मक बनाने और भविष्य के कार्य के संदर्भ में क्षमता निर्माण करने की यात्रा शुरू करने के लिए G20 अध्यक्षता ग्रहण की है। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री द्वारा किया जाएगा और यह टेक्नोलॉजी के लीडरों, इन्फ्लूएन्सर और शिक्षाविदों के लिए अपने दृष्टिकोण और काम के भविष्य के बारे में विज़न दिखाने के लिए एक अद्वितीय प्लेटफार्म होगा।

प्रदर्शनी में विभिन्न सेक्टर्स के प्रतिभागी ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेंगे जो फ्यूचर ऑफ़ वर्क, माडर्न वर्कप्लेस में निरंतर इनोवेशन, पारंपरिक शिल्प में टेक्नोलॉजी को शामिल करने, भविष्य के कौशल और इनोवेटिव डिलीवरी मॉडल को आगे बढ़ाएगी। 26 अप्रैल को, प्रदर्शनी केवल G20 प्रतिनिधियों द्वारा ही एक्सेस की जा सकेगी।

स्विगी डाइनआउट ने 50 प्रतिशत की छूट के

इंदौर में लॉन्च किया ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट फेस्टिवल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के अग्रणी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने पहली बार अपने एप पर स्विगी डाइनआउट के माध्यम से डाइनआउट फ्लैगशिप प्रोग्राम ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट फेस्टिवल को लॉन्च करने का एलान किया है यह ऑफर 4 जून 2023 तक उपलब्ध रहेगा इस फेस्टिवल के 7वें संस्करण के तहत स्विगी डाइनआउट के यूजर इंदौर में 60 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में फ्लैट 50 प्रतिशत छूट की डील का लाभ ले सकेंगे इसके अतिरिक्त उन्हें एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड पर 15प्रतिशत अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा इंदौर में स्वाद के दीवानों को सर्वश्रेष्ठ रेस्टोरेंट में डाइनआउट का मौका देने के लिए स्विगी डाइनआउट ने अनप्लग्ड कोर्टयार्ड हिचकी और द साल्ट कैफे किचन एंड बार जैसे कुछ बड़े रेस्टोरेंट के साथ साझेदारी की है।

स्विगी डाइनआउट के सह-संस्थापक एवं वीपी श्री अंकित मेहरोत्रा ने कहा हमने स्विगी एप पर पहली बार ग्रेट इंडियन रेस्टोरेंट फेस्टिवल को लॉन्च किया है और मैं यह घोषणा करते हुए उत्साहित हूं कि हम अपने यूजर्स के लिए डाइनिंग के एक नए एक्सपीरियंस की राह खोल रहे हैं। इस साझा प्रयास से उन्हें बेहतरीन व्यंजनों को आजमाने का मौका मिलेगा और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी लाभ होगा। स्विगी में हम स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने और अपने ग्राहकों को शानदार डिलीवरी एक्सपीरियंस उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह फेस्टिवल भी इसी का प्रमाण है।'

वर्तमान समय में स्विगी डाइनआउट के साथ 34 शहरों में 21,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट पार्टनर जुड़े हैं और यह भारत में डाइनिंग आउट के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। स्विगी डाइनआउट में फाइन डाइनिंग, लॉउंज बार, पब, कैफे, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट समेत कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्विगी वन मेंबर्स के लिए अतिरिक्त लाभ के साथ यूजर्स बेहतरीन डिस्काउंट भी पा सकते हैं।

कोटक पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी' को लॉन्च

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और इसके सीएसआर सहयोगी पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन फाउंडेशन ने तेलंगाना के गाचीबावली में विश्व स्तरीय बैडमिंटन ट्रेनिंग सेंटर 'कोटक पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी' की शुरुआत की है। इस अवसर पर पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन फाउंडेशन के संस्थापक ट्रस्टी और राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद, ट्रस्टी एल.वी. सुब्रह्मण्यम, और कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालिक निदेशक शांति एकाम्बरम और ग्रुप प्रेसिडेंट व ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जैमिन भट मौजूद रहे। नया लॉन्च किया गया अत्याधुनिक बैडमिंटन सेंटर खेल पर केएमबीएल के कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसे बैंक और भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज, पुलेला गोपीचंद के संस्थापक ट्रस्टी पुलेला गोपीचंद के साझा दृष्टिकोण के साथ विकसित किया गया है। बैडमिंटन फाउंडेशन बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत को और अधिक सम्मान दिला रहा है। बैडमिंटन प्रशिक्षण केंद्र महत्वाकांक्षी और प्रशंसित एथलीटों को शीर्ष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचेज के साथ-साथ उन्नत बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करता है। 2019 में, कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा विकसित करने के लिए पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन फाउंडेशन (फाउंडेशन) के सहयोग से खेल में अपनी सीएसआर परियोजना की घोषणा की। इस नई प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ दोनों संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो देश में असाधारण एथलीटों और कोचेज को विकसित करने की उनके साझा दृष्टिकोण को हासिल करने की दिशा में उनकी यात्रा की शुरुआत के बारे में बताता है।

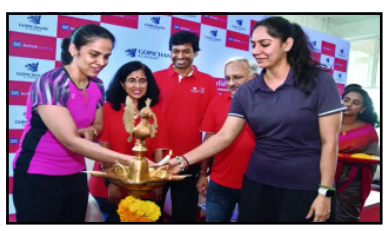

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।